



आवास बंधु

आवास एवं नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

0 Km

NH-24,

Eastern Peripheral
Expressway,

Delhi-Meerut
Expressway



प्रधानमंत्री जन आवास योजना
सरल निवास, सफल विकास

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग
नीति के आधीन

प्रधानमंत्री आवास योजना

के लाभों सहित

गोविन्द पुरम एक्सटेंशन, एन० एच० 24, गाजियाबाद में भवन पाने का
स्वर्णिम अवसर

7 MAY 2017 से 6 JULY 2017

सच्चा घर, सच्चे दाम



**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
द्वारा स्वीकृत**

बहुमंजिले भवनों की योजना



प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन

हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन 2022 तक 'सबके लिए आवास' शुरू किया है। 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना का **प्रधानमंत्री आवास योजना** के नाम से प्रारम्भ किया है।

यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र/ लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।

इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न विकल्पों के माध्यम से शहर के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न एवम् मध्यम आय वर्ग की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है।

गृह आवास में इस मिशन के दो प्रमुख उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है।

1. सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
2. ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडि के माध्यम से कमजोर, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।



BENEFITS

GOVT BENEFITS

No EDC Charges
No Service Tax
Rebate On Stamp Duty
Fixed Flat Sizes
Fixed Maximum Price
Construction As Per Govt.norms

PROJECT BENEFITS*

Special Discount In Price
Free Parking
Free Club Membership
Free Power Backup Upto 1KVA
No IDC charge
No Fire Fighting charge (FFC)
No External Electrification charge (EEC)

PMAY BENEFITS

Savings of up to **2.40 Lakh** through subsidy
in interest on Home Loan under PMAY

CLOSE PROXIMITY

NH-24
Delhi-meerut Expressway
Eastern Peripheral Expressway

SCHOOLS

Radicon School
The DPSG International
Sunder Deep World School
Gurukul The School NH-24, and many more

UNIVERSITIES

Sunder deep Group of Institutions
Bhagwati Institute of Technology & Science
Inmate Institutions
Rama University,
IMS Ghaziabad and many more

***Project Benefits are for limited Period, The Benefits can be removed any time without prior notice.**



SPLS गृह आवास का लक्ष्य कम-से-कम कीमतों पर समाज के “निम्न-मध्य” एवं “मध्य” आय वर्ग को न्यूनतम दो कमरे, रसोई घर, बाथरूम, शौचालय एवं बालकनी की सुविधाओं से परिपूर्ण बहुमंजलिये पक्के आवास उपलब्ध कराना है। जिनमें एक अच्छे बहुमंजलिये भवन वाले प्रोजेक्ट की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों।

“सच्चा घर सच्चे दाम”—हमारा एक प्रयास है जिसके अन्तर्गत हम कम से कम लाभ कमाते हुए, उच्च गुणवत्ता के घर उपलब्ध कराये।

इस योजना में 3 रूम के बहुमंजलिये आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह भवन भूकम रोधि तकनीक जो कि आई.आई.टी. दिल्ली से सत्यापित है, से तैयार किये जाएंगे। जिनका पोजेशन विभिन्न फेजों में दिया जाना प्रस्तावित है।

1. प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभ

PMAY योजना की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता ब्याज सब्सिडी है। जिसका लाभ सीधा ग्राहक के लोन खाते में बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दिया जाएगा जिससे की ग्राहक की मूल राशि अथवा EMI में कमी होगी। निम्नलिखित तालिका ब्याज सब्सिडी की राशि दर्शाती है।

लोन कैटेगरी	लोन अमाउंट	ब्याज में सब्सिडी	EMI में कमी	ब्याज में कुल बचत?
₹ 6 लाख तक	₹ 6 लाख तक	6.5%	₹ 2, 219	₹ 2,46, 625
₹ 12 लाख तक	₹ 9 लाख तक	4%	₹ 2, 158	₹ 2,39, 843
₹ 18 लाख तक	₹ 12 लाख तक	3%	₹ 2, 200	₹ 2,44, 468

कम दरों पर लोन देने का फायदा पहला घर खरीदने वालों को ही मिलेगा। इसके हिसाब से एक परिवार में एक घर का नियम मान्य होगा। परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे आते हैं। सस्ते लोन स्कीम में अप्लाई करते वक्त इस बात का एफिडेविट देना होगा कि परिवार के किसी भी मेम्बर के नाम कोई घर नहीं है। ब्याज सब्सिडी की मंजूरी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल कार्यालय द्वारा दी जाएगी।

2. उत्तर प्रदेश सरकार की अफोडेबल हाउसिंग नीति के लाभ

2 (a) सर्विस टैक्स

इस योजना में सर्विस टैक्स जो की 4.5% हैं, यह सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।

उदाहरण तालिका

	फ्लैट के प्रकार	कीमत*	TAX	योजना में टैक्स
T1	3 रूम सेट (S)	13.50 लाख	₹.60750	NIL

*टोप फ्लोर पर आधारित

2 (b) EDC शुल्क

जो की ₹. 200/-वर्ग फीट तक हैं। वह नहीं लगेगा।

उदाहरण तालिका

	फ्लैट के प्रकार	MSSA *	EDC चार्ज	EDC की कुल देहराशि	योजना के तहत EDC टैक्स की कुल देहराशि
T1	3 रूम सेट (S)	739 sq.ft.	₹.200/-	₹.147800/-	NIL

*MSSA Is Indicative Market Suggested Super Area Of the Flat given for Comparison. So that Customer Can Understand the Super Area Offered In general Practice in Normal Projects. The Price Offering is not on MSSA.



2 (c) रजिस्ट्री शुल्क में छूट

उक्त के संबंध में अभी सरकारी आर्डर/आदेश आने बाकी हैं परन्तु अन्य प्रदेशों में आई अफॉडेबल हाउसिंग नीति में रजिस्ट्री केवल 100 रु के रेवेन्यु स्टॉप पर की गई है।

उदाहरण तालिका

	फ्लैट के प्रकार	कीमत	रजिस्ट्रेशन 7% शुल्क	योजना के तहत रु.
T1	3 रूम सेट (S)	13.50 लाख	रु.94500/-	रु.100

3 प्रोजेक्ट द्वारा दिये गए लाभ

3 (a) बेसिक कीमत पर छूट

क्योंकि यह प्रोजेक्ट सरकारी मानको पर आधारित हैं इसलिए इसकी Maximum Sale Price सरकार द्वारा तय की गई है। परंतु हमारी सोच "सच्चा घर, सच्चे दाम" के अन्तर्गत, कुछ भवनों को और भी कम कीमतों में समाज के सभी वर्गों को देने की हैं।

फ्लैट का आकार	सामान्य कीमत	योजना के अन्तर्गत कीमत	कुल लाभ
3 रूम सेट (S) T1	20.40 लाख	13.50 लाख	6.90 लाख*

*यह स्कीम लिमिटेड फ्लैटों पर लागू है।

3 (b) पार्किंग शुल्क

पार्किंग शुल्क

फ्लैट के आकार	पार्किंग चार्ज	योजना के तहत चार्ज
T1, T2, के लिए स्कूटर पार्किंग	रु.50,000/-	NIL

* प्रथम कुछ आवेदको के लिये।

3 (c) क्लब मेम्बर शुल्क

हम इस प्रोजेक्ट में एक पूर्ण सुसज्जित क्लब का निर्माण यहां के निवासियों के लिए कर रहे हैं। जिसमें एक स्वीमिंग पूल, जीम, इन्डोर गेम्स का प्रावधान सोचा गया हैं, जिसके प्रयोग के लिए मेम्बरशिप अनिवार्य होगी। पहले कुछ आवेदको को निःशुल्क मेम्बरशिप दी जायेगी।

मेम्बरशिप चार्ज	योजना के तहत*
रु.50,000/-	NIL

3 (d) फायर फाईटिंग शुल्क

फायर फाईटिंग चार्ज	योजना के तहत
रु.25,000/-	NIL

3 (e) IDC शुल्क

IDC	योजना के तहत
रु.135000/-	NIL

3 (f) पॉवर बेकअप शुल्क

	सामान्य चार्ज	योजना के तहत
1 KVA	रु.20000/-	NIL



FAQ's

1. योजना का नाम

उ.प्र. सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के आधिन “ ए.पी. एल.एस. गृह आवास ” गोविन्द पुरम एक्सटेंशन गाजियाबाद में, 3 कमरों के बहुमंजिले आवासीय भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण।

2. स्थान

गोविन्द पुरम एक्सटेंशन, जल निगम रोड़, एन०एच०24, गाजियाबाद

3. भवनों के प्रकार

इस योजना में विभिन्न प्रकार के 3 कमरों के बहुमंजिले भवन विकसित किये जाने हैं। भवनों का विवरण प्रोसपेक्ट्स में दिया गया है।

4. भवनों का अनुमोदित क्षेत्रफल

विभिन्न प्रकार के भवनों का क्षेत्रफल बिल्टअप एरिया के आधार पर दर्शाया गया है। अपरिहार्य स्थिति में कब्जे के समय यह क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है।

5. भवनों की अनुमानित संख्या

भवनों की संख्या का विवरण प्रोसपेक्ट्स में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

6. भवनों का अनुमानित मूल्य

भवनों का अनुमानित मूल्य प्रोसपेक्ट्स में दर्शाया गया है। यह मूल्य बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किया जा सकता है।

7. ग्राहता

7.1 आवेदक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

7.2 योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

1. SCHEME NAME

Under U.P. Govt's affordable Housing Scheme- **SPLS Griha Aawas**, Govind Puram Extension, Ghaziabad : For Registration/ allotment of 3 rooms residential houses.

2. LOCATION

The aforesaid scheme is situated in the area of the Govind Puram Extension, Jal Nigam road, NH-24, Ghaziabad

3. TYPE OF FLATS

Different types of 3 Room sets are available under this scheme. The details of Flats are given in Prospectus.

4. ESTIMATED AREA OF FLATS

Built up area of Flats of different types has been mentioned. This area may vary at the time of Possession Culminated due to construction Reason/Permissible limit.

5. ESTIMATED NUMBER OF FLATS

Details of Number of flats is given in Prospectus, number of flats can be changed without any prior information.

6. ESTIMATED COST OF FLATS

Estimated Cost of the Flat is mentioned in Prospectus. It can be changed without any prior information.

7. ELIGIBILITY

7.1 The applicant must be a citizen of India.

7.2 Applicant should not be less then 18 years old on the last date of submission of application form.



7.3 आवेदक या उसका परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/ पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) उ.प्र. सरकार की अफोर्डेबल आवास योजना में एक से अधिक अफोर्डेबल भवन का आवंटन प्राप्त नहीं करेगा।

7.4 जिन व्यक्तियों ने उ.प्र. शासन द्वारा जारी अफोर्डेबल हाऊसिंग नीति के आधीन आवास योजना के अंतर्गत पहले से ही पंजीकरण करवाया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करा आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अंतर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में करना होगा।

7.5 यदि किसी व्यक्ति अथवा परिवार के अश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा अफोर्डेबल भवन में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को ही रख सकता है।

8. आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र/ विवरण पुस्तिका नियम व शर्तों सहित बैंकों की प्रमुख शाखाओं से रु. 200/- के नगद भुगतान पर प्राप्त अथवा वेबसाइट www.grihawas.com से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि के चैक/ बैंक ड्राफ्ट सहित उपरोक्त बैंकों की शाखाओं में जमा कराये जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट/ चैक "SPLS AAWASIYA YOJNA" के पक्ष में देय तथा संबन्धित शहर की बैंक शाखा में भुगतान योग्य होना चाहिए। डाउनलोड की गई विवरण पुस्तिका के आवेदन पत्र के साथ रु. 200 का ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है।

9. आवंटन

पंजीकृत आवेदकों के भवनों का आवंटन लॉटरी / ड्रॉ के द्वारा किया जायेगा। असफल आवेदकों की पूर्ण पंजीकरण धनराशि बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाइन माध्यम से बैंकों द्वारा वापस की जायेगी। लॉटरी / ड्रॉ के आधार पर सफल आवेदकों को भवन के अनुमानित मूल्य का कुल 10 प्रतिशत सफलता पत्र/ ईमेल के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर चैक/बैंक ड्राफ्ट /ऑनलाइन के द्वारा जमा कराना होगा। कुल 10 प्रतिशत धन राशि प्राप्त होने के पश्चात् भवन का आवंटन सफल आवेदक को कर दिया जायेगा।

7.3 The applicant or his/her/family (family means applicant, his wife/her husband and minor children) must not hold more than one house developed under Affordable Awas Yojna of U.P. Govt.

7.4 Persons who are already registered under U.P. Govt. affordable Housing Scheme but house has not been allotted, may also apply under this Scheme by paying registration amount. Such applicants will be considered at par with other in this scheme. These applicants must clearly mention their old registration number and scheme details.

7.5 If a person or his / her family gets allotment of more than one affordable house than they can keep only one of them.

8. HOW TO APPLY

The registration application form will be available in major branches of Banks on cash payment of Rs. 200.00 only and can also be downloaded from website www.grihawas.com. The duly filled and signed application form along with Cheque/ DD may be deposited into above mentioned bank branches. Cheques, Bank draft would be in favour of "SPLS AAWASIYA YOJNA" and payable at the branches of the bank where forms are to be deposited. Downloaded Applications must be deposited with a draft of Rs. 200.

9. ALLOTMENT

Allotment of houses is based on lottery/ draw. Unsuccessful applicants will get refund of their full registration amount through DD, online Payment by banks. Successful applicants have to deposit 10% of the total cost of the Flat as allotment money within 15 days from the date of Confirmation letter through cheque, DD after adjusting earlier paid registration amount. Allotment letter will be issued after clearance of 10% amount of the total value of Flat.



10. किश्तें:

आवंटन पत्र जारी होने के उपरांत शेष 90 प्रतिशत धनराशि 11 निर्माण आधारित किश्तों के द्वारा समय-समय पर जमा करानी होगी।

आवेदक की वित्तीय स्थिति के आकलन के पश्चात् बैंक द्वारा सुविधा के अनुसार ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ऋण का देय ब्याज का भुगतान आवंटी को स्वयं करना होगा।

11. पेनल ब्याज

यदि देय किश्तों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो आवंटी को देय धनराशि का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक दर से पेनल ब्याज सहित जमा करना होगा। पेनल ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी।

12. समर्पण/ निरस्तीकरण

12.1 यदि कोई आवेदक भवन का आवंटन होने के बाद आवंटित भवन का समर्पण करता है, इस स्थिति में फ्लैट की कुल कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि काटकर बाकी राशि वापिस करने का प्रावधान है। धनराशि वापिसी हेतु आवंटी को समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद वापिस जमा करानी होगी।

12.2 भुगतान विवरण के अनुसार दो किश्ते लगातार जमा न कराने की दशा में भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा तथा ऐसी दशा में मकान की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। धनराशि वापिसी हेतु आवंटी को समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद वापिस जमा करानी होगी।

12.3 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो 5 रु. प्रति वर्ग फीट पर प्रतिमाह मेन्टीनेंस शुल्क देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष इस शुल्क में 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी की जाती रहेगी एवं 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जा सकता है, शर्तें एवं नियम के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

10. INSTALLMENTS:

After the issue of allotment letter the balance 90% amount shall be payable in 11 instalments based on Construction Link Plan mention in Prospectus.

Based upon the financial eligibility of applicants the banks may provide facility of loan to pay quarterly installment or to pay installments of construction link plan (CLP). However the bank interest will be paid by the applicants.

11. PENAL INTEREST

If the Instalment payable is not paid within time, penal interest @ 18% per annum shall be paid along with the payment amount. Penal interest will be calculated on day basis.

12. SURRENDER/CANCELLATION

12.1 If an applicant surrenders the allotment or allotted Flat, then 10% of the total value of the Flat shall be forfeited and the balance amount shall be refunded without any interest. All original documents & receipts will have to be submitted by the applicant for refund.

12.2 The developers shall have the right to cancel the allotment of flat as per the rule if there is default in payment of two consecutive installments according to the payment schedule. in that case 10% registration amount will be forfeited and the balance amount will be refunded without any interest. All original documents & receipts will have to be submitted for refund.

12.3 If the allottees does not take the possession of the flat on due date, maintenance charge of Rs.5/sq.ft. per month shall be charged and will be increased automatically by 10% every year from 1st April. In case the possession is not taken till three months from the due date. allotment shall be cancelled and action shall be taken as per clause and the balance amount would be refunded without interest.



13. ड्रा होने की स्थिति में

13.1 योजना के ड्रा के समय उपस्थित रहने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में ड्रा निकालकर भवन का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों / वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

13.2 जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं उन्हें ड्रा के पश्चात पंजीकरण राशि बिना ब्याज के 6 माह के अंदर वापिस कर दी जाएगी।

13.3 यदि इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि के 6 माह के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा छह माह के पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से धनराशि की वापसी की तिथि तक आवेदक को 12 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

13.4 जिन आवेदकों को ड्रा में सफलता प्राप्त होती है एवं वह उसे स्वीकार नहीं करते हैं या स्वीकार करने के बाद 15 दिन के अन्दर पहली किस्त जमा नहीं करते हैं, तो इस दशा में आवेदक की पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण केस 1थ-साथ 1वनक 1अ 1वटर्न1 नरस्तक र1 दयाज 1एगाए वं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

15. कब्जा:

15.1 इस योजना में भवन का कब्जा निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात भिन्न-भिन्न फेजों में एवं आवंटि द्वारा कुल मूल्य/ अन्य शुल्क की राशि, जमा करवाने तथा विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा जिसका व्यय आवंटि द्वारा वहन किया जायेगा।

13. In Case of Draw

13.1 The allotment of house will be made by a lottery draw in the presence of the applicants, who wish to be present. No information of the date & place of lottery/ draw will be given specifically to any person. The aforesaid information will be published in the news paper/on website. No claim for specific Floor/ house will be accepted of any applicant.

13.2 The unsuccessful applicants in lottery draw for allotment will get full refund of their registration amount within 6 months from the date of the draw without any interest.

13.3 Due to any unforeseen reasons If the lottery draw for allotment is held after 6 months from the last date of registration then 12% simple interest will be given from the last date of registration till date of payment.

13.4 If successful applicants in lottery / draw Refuses to accept the unit or after accepting doesn't pay 1st instalment within 15 days, in this case applicant's Application Money will be forfeited.

14. Fake presentation or suppression of facts

If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment will be cancelled and his/her registration amount shall be forfeited.

15. POSSESSION :

15.1 Possession of the flat in this scheme shall be given in phases after completion of development work and payment of total amount /other charges and lease rent amount and registration of sale deed by him/her. The cost of sale deed shall be borne by the allottee.



- 15.2** प्रश्नगत योजना में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 के प्रावधान लागू होंगे।
- 15.2** The Uttar Pradesh Apartment act 2010 will be applicable to the scheme.
- 15.3** यदि कोई भी स्थानीय निकाय एवं अथोर्टी किसी भी नये चार्ज को लागू करता है, तो उसका भुगतान आवंटी द्वारा समय-समय पर करना होगा।
- 15.3** Allottee shall pay all the municipal taxes and other taxes which may be charged by Government or any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession.
- 15.4** आवंटी विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन व सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।
- 15.4** Allottee, himself/herself, will take electricity/water connection related to the concerned department at his/her own expenses.
- 16.** आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त, 3 महीने के अंदर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर, अपने खर्च पर भवन का विक्रय विलेख पंजीकृत कराना होगा। आवंटी उ.प्र. शासन की नीति के अनुसार रजिस्ट्री शुल्क में छूट उपलब्ध प्राप्त कर सकता है।
- 16. LEASE DEED:**
Allottee, at his/her own cost must complete all formalities and get the sale deed executed within three months after paying full cost of the property.
- 17. भवनों का प्रयोग**
आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।
- 17. USE OF FLATS**
The flats shall be used for residential purpose only by the allottee.
- 18. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं**
- 18. OTHER IMPORTANT NOTICES**
- 18.1** इस योजना में भवनों के आवंटन से पूर्व किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार परियोजना के विकासकर्ता को होगा। तथा ऐसे संशोधन आवेदकों / आवंटियों को मान्य होंगे।
- 18.1** Before the allotment of houses any terms and condition of the scheme may be revised by the developer and the same would be applicable to applicants/ allottees.
- 18.2** प्रोस्पेक्टस में दर्शाये गये भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के कब्जा के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा।
- 18.2** Area of flats shown in Prospectus may change. At the time of actual Possession of the scheme change in area is possible which will finally be informed to the allottee.
- 18.3** प्रोजेक्ट के पोजेशन की तिथि क्या है?
परियोजना का कब्जा विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, पहले चरण का कब्जा सफल आवंटन की तारीख से 36 महीने के भीतर दिया जायेगा। 6 महीने की एक विस्तारित अवधि के साथ। देरी के मामले में पेनल्टी चार्ज है।
- 18.3** What is the date of possession of the Project.
The Possession of the Project will be given in Phases, 1st Phase of Possession will be given within 36 months from the date of successful Allotment with an extended Period of 6 months.



18.4 देरी के मामले में पेनल्टी चार्ज क्या है?

इसमें देरी के मामले में पेनल्टी चार्ज 5 रु./ प्रति वर्ग फीट प्रति माह है।

18.4 What is the penalty clause in case of delay?

There is a Penalty clause in case of delay which is Rs. 5/- per sq. ft. per month.

18.5 क्या यह प्रोजेक्ट किसी प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त है।

परियोजना आवास बंधु, आवास एवम् नियोजन विभाग, उत्तर-प्रदेश सरकार लखनऊ और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है।

18.5 Is the project approved from the concerning Authority?

The Project is Approved from Awas Bandhu, Lucknow and Ghaziabad Development Authority.

18.6 इकाइयों के हस्तांतरण नीति क्या है?

हस्तांतरण के मामले में, उ.प्र. अफोर्डेबल आवासीय योजना और प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत लाभ सरकार के विवेकाधिकार के अनुसार निर्धारित होगा।

18.6 What is the Transfer/ Endorsement policy of the units?

In case of Transfer, benefits under U.P. Govt's Affordable Housing scheme & Pradhan Mantri Awasiya Yojna may not continue as per te sole discretion of the government.

19. योजना में नियमअनुसार आरक्षण की सुविधा भी प्रस्तावित है।

- | | |
|---|-------|
| 1. सामान्य श्रेणी | - 50% |
| 2. केंद्र / राज्य सरकारी कर्मचारी | - 25% |
| 3. सशस्त्र सेनाबल कर्मचारी | - 15% |
| 4. सेवानिवृत्त सार्वजनिक / प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी | - 05% |
| 5. शारीरिक रूप से विकलांग | - 05% |

19. Categories for Reservation Proposed for Applicants.

- | | |
|--|-------|
| 1. General Category | - 50% |
| 2. Central / State govt. Employee | - 25% |
| 3. Armed Forces Employee | - 15% |
| 4. Retired Public / Pvt. Sector Employee | - 05% |
| 5. Physically Challenged | - 05% |

Reference

hindustantimes

NHAI sets October deadline for 22km stretch of Eastern Peripheral Expressway



The ring road-like expressway will pass through Greater Noida, Ghaziabad, Faridabad and parts of Delhi. It is likely to take at least 70,000-80,000 vehicles off Delhi roads (HT Photo)

National Highways Authority of India (NHAI) officials on Thursday said they have resolved land issues of most farmers for the Eastern Peripheral Expressway (EPE) and set an October deadline for the completion of the part that falls in Gautam Budh Nagar. A 22km stretch of the 135km expressway that falls in Gautam Budh Nagar.

The ring road-like expressway will pass through Greater Noida, Ghaziabad, Faridabad and parts of Delhi. It is likely to take at least 70,000-80,000 vehicles off Delhi roads. The NHAI needed land from 39 villages in Gautam Budh Nagar for the expressway, which was proposed in 2005.

On February 24, 2016, farmers in Bil Akbarpur had held a team of engineers and workers captive, demanding hiked compensation. Farmers had disrupted work on the project in 2015, causing delays. Farmers also protested against the alignment of the expressway as it necessitated demolition of few houses in Greater Noida's Bil Akbarpur village.

"We have resolved issues of most of the farmers and work on the project is in full swing. The Supreme Court directed the government to complete this crucial project in 2018, but we have set October 2017 as the deadline. We will complete it successfully by then," Kishore Kanyal, NHAI project director for the EPE project said.

NHAI has roped in Ashoka Buildcon Ltd for constructing the 22km stretch. A budget of Rs800 crore has been allocated for the stretch.

"The district magistrate of Gautam Budh Nagar, NP Singh, recently held a meeting with farmers to resolve their issues. We have decided to tweak the alignment of the expressway so that there is no need to demolish any farmer's residence in Bil Akbarpur. I believe most of the farmers' issues are resolved," Kanyal said.

The Gautam Budh Nagar administration is in the process of distributing compensation to farmers.

A small section of farmers, however, is still unhappy with the land compensation given by the government.

"We were demanding Rs5,508 per sqm. They had initially offered us Rs850 per sqm and after negotiations, they paid Rs3,500 per sqm. We have filed pleas in Allahabad high court because the government is discriminating in giving compensation. The government has given Rs4,700 per sqm to farmers in neighbouring Ghaziabad district. The rate should be the same. If the compensation is not revised, many farmers will not give their land for the project," Teja Gurjar, a farmer leader, said.

ईस्टर्न पेरिफेरल बदलेगा तस्वीर

केंद्र सरकार की कदम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे-धे पोअरेक्ट में तेजी आने की उम्मीद जारी है। इससे गाजियाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा आदि पुराने में डिजिटलमेंट को नई रूपांतर मिलेगी। कड़ी, रोजगार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की समस्या में ज़्यादा सुधार होगा। सख्त ही, दिल्ली में बिना एने ही उदाक कितो भी धर पर आसानी से जाया जा सकेगा। एपसीटी ने इकावार को डेक थिया एपसीटी में ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल का स्टैटस।

135 06
का संभारण एपसीटी में-3 की संभारण

07 2010
सुखी संभारण केंद्र एपसीटी में

03 2675
सख्त संभारण केंद्र की संभारण

01 120
सख्त संभारण केंद्र की संभारण

गाजियाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा-बागपत सीधे जुड़ जाएंगे हरियाणा से

एपसीटी का के लिए देना रिंग राउट

गौतमबुद्धनगर : सिर्फ 6 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण है बाकी एपसीटी में

वेस्टर्न पेरिफेरल का भी इंतजार हुआ लंबा

फरीदाबाद : किसानों का ही कच्चा

www.bhtpi.com

CONNECTIVITY OF EASTERN PERIPHERAL EXPRESSWAY



NEWS UPDATES

Reference

hindustantimes

South Delhi to get signal-free access to Meerut Expressway



Commuters from south Delhi may get signal-free access to the under construction Delhi-Meerut Expressway as the government has tweaked the proposal for a flyover near Indraprastha Park giving it an additional loop towards NH 24. While the expressway is expected to reduce the travel time between Delhi and Meerut to 45 minutes from the present three hours, the Indraprastha Park flyover will save another 10 minutes.

The proposed flyover near Indraprastha Park will save time as well as reduce traffic snarls on the stretch. (Mohd Zakir / HT FILE) towards Pragati Maidan and ITO from Ashram. "We already have

The flyover had been initially planned by the Public Works Department (PWD) to provide quick access to those headed

a carriageway in operation which benefits those going from north to south Delhi. The flyover near Indraprastha Park was initially being planned parallel to it for the traffic coming from the other side," a senior PWD official said.

However, after the announcement of the expressway, the National Highway Authorities of India (NHA) also wanted to build a flyover at the same spot. Last week, chief secretary MM Kutty held a meeting with both the agencies and asked them to sort out the issue. "The solution is to build the flyover with a loop towards NH 24. Now, commuters coming from Ashram side will take the flyover at Sarai Kale Khan and then the proposed flyover in front of Indraprastha Park. This flyover will be for people going straight towards north Delhi and for those wanting to take NH 24 or Meerut Expressway," the official added.

Sources said the flyover will be constructed by NHA and is likely to be completed in three years. The construction on 74-km-long Delhi-Dasna-Meerut 14-lane expressway has started. Prime Minister Narendra Modi on December 31, 2015 had unveiled a plaque to mark the laying of the foundation stone of the Delhi-Meerut Expressway to be built at a cost of 7,566 crore. The Delhi-Meerut Expressway will be an access-controlled highway. Nearly, 31 traffic signals have been removed from the stretch.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015
TIMES CITY

50km of 14 lanes in 30 months

Seven-Year-Old Plan To Be Finally Set In Motion By PM Modi On Dec 31

WIDENING OF NH-24 (DELHI TO HAPUR)

STRETCH I: Nizamuddin bridge to UP border
LENGTH: 8.7km
SCORE: 6-lane expressway and 8-lane highway, including bridge on Yamuna

STRETCH II: UP border to Dasna
LENGTH: 15.3km
SCORE: 6-lane expressway and 8-lane highway

STRETCH III: Dasna to Hapur bypass
LENGTH: 22.3km
SCORE: 6-lane highway

► No need to acquire fresh land
► Funds not an impediment
► Deadweight: 30 months

The other eight lanes—four on each side—might be a normal highway and commuters would have to pay toll. The last study of traffic on this stretch was done in 2008 and it was found that nearly 14 lakh passenger cars will use this corridor. A survey by RTI has shown how traffic growth was about 20% more than the capacity. Now it has become worse as huge number of housing societies have sprung up on both sides of the highway and in the absence of any viable public transport system, a large number of commuters use personal vehicles.

The widening of this stretch will increase throughput of vehicles and so tolling will reduce pollution. Since in hybrid annuity model, the government takes all the risks and developers are assured of getting back their investment in installments, the project will be completed on time, said a highway ministry official.

Delhi, Dec 30 In what will finally serve as a big relief to lakhs of commuters using Nizamuddin Bridge on the major stretch of NH-24, widening of this corridor will start from next month. Prime Minister Narendra Modi is likely to lay the foundation stone on December 31.

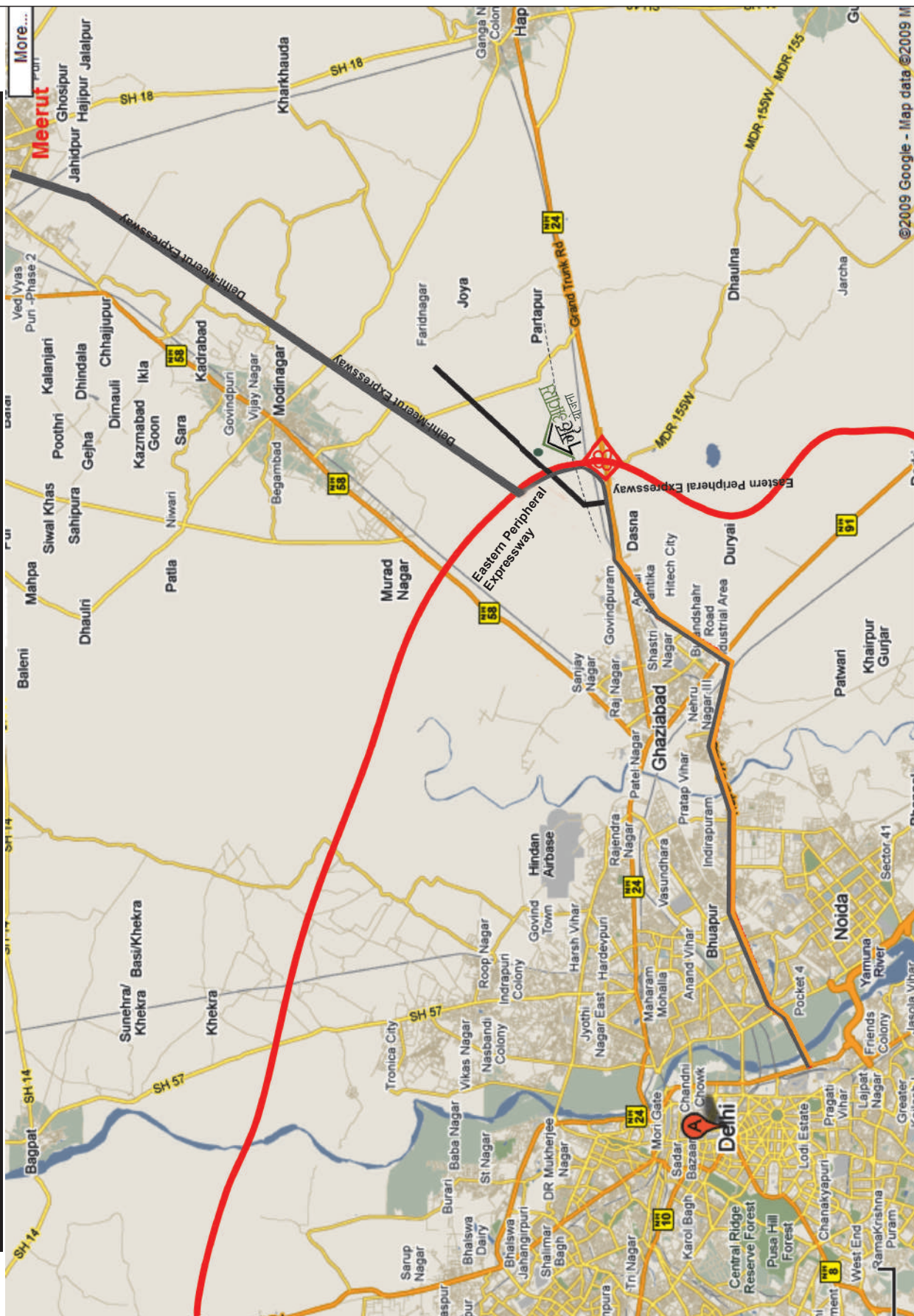
Expansion of one of the most congested stretches in the NCR will be implemented through the first anniversary of a new variant of public-private partnership (PPP) model, which allows construction of roads by developers and thereby eliminating delays in construction.

For faster execution, the entire 24-km stretch has been divided into three parts. The first two portions — Nizamuddin Bridge to UP Gate and UP Gate to Dasna — will be widened to 14 lanes and the second 16 km stretch of this will be barricaded earlier for straight going traffic. The remaining portion will be

an NHAI official. "We have received bids for the two portions and bids for the third one will be opened soon. The process will be over in the next 30-45 days so that contractors are awarded quickly," he

Communities will have to pay toll to use the barricaded stretch due to limited entry and exit points. The official said for seamless traffic assessment and avoid pile-up at toll plazas, the toll will be complete electronic toll collection (ETC) system on this stretch. The commuters will have to pay toll for taking the barricaded stretch, which is an expressway and the design speed will be 100kmph.

CONNECTIVITY ON EASTERN PERIPHERAL & DELHI-MEERUT EXPRESSWAY





SALIENT FEATURES

Spacious Wide Balconies.

Jogging Track.

Lush Landscaping And Extensive Plantation.

Adequate Fire Fighting System On Each Floor.

24 Hours Power Backup For Essential Services.

24 Hours Gated Security With CCTV Surveillance.

High Speed Lift With Intercom Facility.

Shopping Centre For Daily Needs.

Rain Water Harvesting System.

Power Backup up to 1Kva.

CLUB

Fully Functional club with :

Swimming Pool

Gymnasium

Badminton court

Basket Ball Court

Carom Board Room

Table Tennis

SITE



LEGEND:-

- T-1 2 BHK + 1 TOILET (SMALL)
- T-2 2 BHK + 1 TOILET
- T-3 2 BHK + 2 TOILET

- 1. ENTRY / EXIT RAMP FROM BASEMENT
- 2. COMMERCIAL
- 3. COMMUNITY
- 4. SCHOOL
- 5. JOGGING/CYCLE TRACK
- 6. SWIMMING POOL

LAYOUT



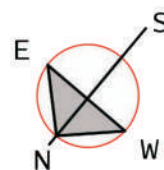
7. BASKETBALL COURT

8. BADMINTON COURT

9. PARKING

10. GREEN LAWN

11. GUARD ROOM



FLOOR PLANS

T1

3 Room Set

2 Bed Room + Living Room
+ Kitchen + Toilet

*MSSA	739 sq.ft
BUILT UP AREA	528 sq.ft
CARPET AREA	465 sq.ft

1 sq.mtr. = 10.76 sq.ft.



T2

3 Room Set

2 Bed Room + Living Room
+ Kitchen + Toilet

*MSSA	822 sq.ft
BUILT UP AREA	587 sq.ft
CARPET AREA	519 sq.ft

1 sq.mtr. = 10.76 sq.ft.



T3



3 Room Set

2 Bed Room + Living Room
+ Kitchen + 2 Toilet

*MSSA	1011 sq.ft
BUILT UP AREA	722 sq.ft
CARPET AREA	644 sq.ft

1 sq.mtr. = 10.76 sq.ft.

***MSSA is indicative Market Suggested Super Area of the Flat given for Comparison. So that customer can understand the Super Area offered in general Practice in Normal Projects. The Price Offering is not on MSSA.**

Carpet area of an Affordable Housing Unit: (Reference Clarificaton NO-S.M.A.Y 12/2016/119/Eight-1-16-34 Meeting /2014)

“Carpet Area” means the net usable floor area of an apartment/dwelling excluding the area covered by the inner and outer walls. It will include area of the living room(s), bedroom(s), kitchen, lavatory(s), bathroom(s) and balcony/ verandah, if provided. It is the actual useable area of an apartment/dwelling unit.



SPECIFICATIONS

STRUCTURE	Earthquake Resistant R.C.C. Frame
LIVING-DINING BEDROOM	<p>FLOORING - Vitrified tiles</p> <p>WALL - OBD/Acrylic Emulsion over cement plaster finished.</p> <p>DOOR - Hardwood frame with Flush Door/Skin Molded Door.</p>
MASTER BEDROOM	<p>FLOOR - Vitrified tiles.</p> <p>WALL - OBD/Acrylic Emulsion over cement plaster finished.</p> <p>DOOR - Hardwood frame with Flush Door/Skin Molded Door.</p>
KITCHEN	<p>FLOOR - Vitrified tiles.</p> <p>WALLS - Combination Of designer ceramic tiles 2' above the working counter.</p> <p>FIXTURES - Good quality stainless steel sink.</p>
TOILETS	<p>FLOOR - Ceramic tiles.</p> <p>WALLS - Designer glazed tiles upto 7'</p> <p>FITTING - Superior quality CP fittings.</p>
ELECTRICAL	Copper wiring in concealed PVC conduits. switches for light & power points. TV and Telephone points in all bedroom & drawing/dininig.
WINDOWS	Wooden Window frames.
DOOR	Designer door at the main entrance.
BALCONY	Anti skid ceramic tiles.
LIFT	Modern high speed elevators.



UNDER U.P GOVT'S AFFORDABLE HOUSING SCHEME Price List for Draw

	3 ROOM SET 2 BHK + 1T	3 ROOM SET 2 BHK + 1T	3 ROOM SET 2 BHK + 2T
TYPE	T1	T2	T3
MSSA*	739 sq.ft.	822 sq.ft.	1011 sq.ft.
BUILT UP AREA	528 sq.ft.	587 sq.ft.	722 sq.ft.
CARPET AREA	465 sq.ft.	519 sq.ft.	644 sq.ft.
PRICE IN LAKH	13.50	15.00	18.50
APPLICATION MONEY	20000	25000	30000

1 sq.mtr. = 10.76 sq.ft.

PAYMENT PLAN FOR SUCCESS FULL APPLICANTS

1.	Within 15 Days(including Application Money)	10%
2.	Within 45 Days	10%
3.	Start of Excavation	10%
4.	Start of Foundation Raft Casting	10%
5.	On basement roof slab	10%
6.	On Casting of 1st Floor Slab	10%
7.	On Casting of 3th Floor Slab	7%
8.	On Casting of 5th Floor Slab	7%
9.	On Casting of 7th Floor Slab	7%
10.	On Casting of 9th Floor Slab	7%
11.	On Start of External Plaster	7%
12.	On Offer of Possession	5%

• FREE OF COST

Parking

3 ROOM SET (T1) – Two Wheeler Parking

3 ROOM SET (T2) – Two Wheeler Parkin

3 ROOM SET (T3) – Open Car Parking

- Fire Fighting Charges (FFC)
- All CP Fitting in all Bathrooms
- 1 KVA Power Backup (worth Rs. 20,000/-)
- Club Membership
- No External Electrification charge (EEC)

*MSSA Is Indicative Market Suggested Super Area Of the Flat given for Comparison. So that Customer Can Understand the Super Area Offered In general Practice in Normal Projects. The Price Offering is not on MSSA.

TERMS & CONDITIONS

- Price List & payment plan can be changed without notice at sole discretion of the company.
- The Flat booking price shall be firm. No esclasion on price once booked.
- The terms & conditions of sale herein are only indicative and are subject to detailed terms and conditions of application form and flat allotment letter.
- Cheque / Pay order / Bank Draft should be in the favour of “**SPLSAAWASIYA YOJNA**”
- Any charges levied or increased by the govt in future shall be payable by applicants.

APPROACH PLAN

- Existing Roads
- Under Construction Roads





APPLICATION FORM

I/We as mentioned below am/ are interested in Applying for a unit in your project **SPS Grihawas**. our Particulars are as under.

SOLE OR FIRST APPLICANT (S) Mr./Mrs./Ms.

S/W/D of.

Nationality. DOB. Profession.

Resident Status : Resident/Non - Resident/Foreign National of Indian Origin.

Income Tax Permanent Account No.(PAN No.)

Occupation. Department(if any).

Annual Income. Email.

Mobile. PhoneNo.

Present / Communication Address.

City. State. Pin.

Permanent Address.

City. State. Pin.

Office Address.

City. State. Pin.

JOINT OR SECOND APPLICANT (S)

Mr./Mrs./Ms.

S/W/D of.

Nationality. DOB. Profession.

Resident Status : Resident/Non - Resident/Foreign National of Indian Origin.

Income Tax Permanent Account No.(PAN No.) Occupation.

Department(if Any) Annual Income.

Email Mobile. PhoneNo.

Present / Communication Address.

City. State. Pin.

Permanent Address.

City. State. Pin.

Office Address.

City. State. Pin.

Category Applied for (FAQ's Point no. 19)

Attach documents for applied category.

Dear Sir, I/We undersigned that a flat may be allotted to me/us as per the company terms and conditions which I/We have understood and shall abide by the same as stipulated by the company.

Sign 1st Applicant

Sign 2nd Applicant



TERMS AND CONDITIONS

1. Nature of Booking.

- Applicant must be citizen of India and must be 18 years of age or older at the time of registration
- For self-contained flats there is no income limit.
- Obtain registration form and follow instructions to fill up.
- Submit registration form before due date and deposit required amount.

2. Registration & Other Charges

- Registration Charges, Stamp Duty, Charges and incidental expenses there to as application at the time of registration shall be extra and is to be borne by the purchaser.
- Other Statutory Charges and taxes as applicable, Levied or Increased from time to time shall be extra and are to be borne by the purchaser.

3. Mode of Payment

- All payments from outstation locations are to be paid through Drafts / Cheque / RTGS / NEFT / local cheques are to be made payable to The "SPLS AAWASIYA YOJNA". purchaser must insist on a duly signed receipt from authorized personnel.
- That the schedule of installments under Payment Plan shall be final and binding on the intending Allottee(s). It is made clear that time for payment is the essence of this allotment.
- That in exceptional circumstances, the Builder may, in its sole discretion condone the delay In payment by charging interest @ 18% per annum. In the event of the Builder waiving the right of forfeiture and accepting the payment on that account, no right whatsoever, would accrue to any other defaulter intending Allottee(s).

4. Delayed Payments

- Interest at the rate of 1.5% per month shall be charged on all delayed payments of installments.

5. Cancellation Charges.

- The Cancellation Charge Will be 10% of Total Amount of the Flat.

6. Additions & Alterations

- Cost of any additions and alterations made over and above specification mentioned in the brochure at the request of the purchaser shall be charged extra.
- If number of applicants is more than available units then draw system will be adopted by lottery. Unsuccessful applicants will receive refund of deposit without interest in case of draw is there with in 6 Months of clearing of payment of the applicant and if it is more than 6 month then interest of those months will be given @ 12%.P.A.
- Name of applicant cannot be changed in registration form or processes thereafter if allotment is made.

7. Possession

- Since it is large project having number of buildings, the construction will be completed in phases. All the major common facilities will be completed only after completion of construction of all the phases. As such the intending Allottee(s) must take the possession of his/her/their own flats as soon as it is made available for possession.
- That the developer shall complete the development / construction of the Flat as per the date mentioned in Allotment Agreement with an extended period of 6 months thereof. In case of delay in construction of the said Flat attributable of delay of Developer, the Developer would pay a sum at the rate of Rs. 5/- per sq. ft. on the built up area per month for the delay beyond three months to the intending Allottee, provided however that the intending Allottee has made payment of all installments towards the sale consideration amount of the said Flat in time and without making any delay to the Developer.
- That in case the intending Allottee(s) fail to take possession of apartment within 'Fit-out-period', he/she/they will pay penalty as per clause mentioned herein after.
- That in case the intending Allottee(s) fail to take possession of Apartment within given "Fit-out-period", Rs 5/-per sq. ft. Per month will be charged and will be increased automatically by 10% every year from 1st April. in case the possession is not taken till three months from the due date, allotment shall be cancelled and action shall be taken as per clauses and the balance amount would be refunded without interest.
- The company shall handover the possession of the completed Flat to the purchaser only on payment of all dues to the company.

8. Changes in Drawings/ Designs

- Due to any unforeseen requirement of authority/company, company has every right to change the design/s and specification/s.

Sign 1st Applicant

Sign 2nd Applicant



DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION FORM:

1. Employment ID; 2. Copy of PAN Card; 3. Address Proof; 4. Photograph of all Applicants; 5. Booking Cheques

Note: This registration form will be governed / superseded by a buyer agreement & the terms contained therein .

b) That if for any reason, whether within or outside the control of the Builder, the whole or part of the scheme is abandoned, no claim will be preferred, except that money received from the intending Allottee(s) will be refunded in full, without interests.

9. Other Terms and Conditions

a) Other terms and conditions mentioned in Allotment Agreement shall apply.

b) In case, the flat is completed before the scheduled date of completion, the entire balance outstanding as on such date of completion shall become due and payable, notwithstanding the installments and due dates mentioned herein.

c) In case of down payment plan, if the purchaser fails to pay the installments in the promised time frame, the payment plan will be automatically considered as flexi link/construction linked plan whichever available. Also the down payment rebates or any other discount will be taken off.

d) If successful allottee does not make full payment within the prescribed time limit the registration will be cancelled and deposit will be refunded after appropriate deduction of cancellation charges. Once allotment is complete and payment is done allottees must follow procedure for sale deed and registration and pay appropriate fees. If possession is not taken within specified time then penalty will apply.

10. Open Car Parking in case of Type T3 Units and Scooter Parking in case of Type T1 & T2 Units shall be given as per the availability on first come first serve basis. These parking space does not transfers right of ownership of the space and it is not part of any sale amount. however applicants of T1, T2, & T3 units who can not get the parking, they can apply for covered parking on additional cost.

11. That the intending Allottee(s) has/have to pay monthly Maintenance charges as decided by the builder at the time of offer of possession to the Maintenance Body of the project Apartment or any other ground whatsoever.

a) That the Interest Free Security Deposit given by the intending allottee(s) to the Builder or nominee of the Builder is transferable to the intending Allottee(s) / Resident Welfare Association (RWA) at the time of termination of the "Maintenance Agreement" or transfer of maintenance to the RWA of the Complex. At the time of handing over of maintenance of the Project/Complex the charge over the following will be handed over to the RWA.

I) All existing lifts, corridors, passages, parks underground & overhead water tanks, fire fighting equipment with motors and motor room.

II) Security gates with intercom, lift rooms at terrace without terrace right.

Note. Open spaces, lobbies, staircases, lifts, terraces, roofs, spaces for commercial. parks, parking spaces (except what has been allotted by an agreement to intending Allottee(s) or tot-lots, space for public amenities. shopping centres or any other space will remain the property of the Builder.

12. That the intending Allottee(s) is aware that various apartment are being allotted to various persons under uniform terms and conditions. The intending Allottee(s) agrees that he will use the said apartment for residential purpose and shall not use the aforesaid apartment for any other purpose which may or likely to cause nuisance to intending Allottee(s) of other apartments in this Complex, to crowd the passages or to use it for any illegal or immoral purpose.

13. That the Apartment shall be used for activities as are permissible under the Law.

14. In the event of any dispute whatsoever arising between the parties in any way connected with the allotment of the said apartment, the same shall be referred to the sole arbitration of a person to be appointed by the 'BUILDER' . The intending Allottee(s) hereby confirms that he/she/they shall have no objection to this appointment and the decision of the arbitrator will be final and binding on all parties. The arbitration proceedings shall always be held in the city of Ghaziabad, India. The Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments/modifications shall govern the arbitration proceedings thereof for the time being in force. The Allahabad High Court and the Courts subordinate to it alone shall have jurisdiction in all matter arising out of or touching and/or concerning this allotment.

15. That in case of NRI/Foreign National intending Allottee(s) the observance of the provision of the Foreign Exchange Management Act 1999 and any other law as may be prevailing shall be responsibility of the intending Allottee(s).

16. That in case, the intending allottee makes any payment to any other person/company, except "SPLS AAWASIYA YOJNA". against his/her/their booked flat, then the intending allottee will be solely responsible and liable for the said payment. Signature of First Applicant
Signature of Second Applicant.

a) If applicant does not disclose full details or gives false information his registration may be cancelled and he will not be eligible for refund of deposit.

b) For income calculation, total income of family including that of spouse and children is considered.

17. If successful applicants in lottery / draw for allotment Refuse to accept the allotted unit or after accepting doesnt pays 1st instalment within 15 days, in this case the units will be canceled and applicant's Application Money will be forfeited.

Sign 1st Applicant

Sign 2nd Applicant

